पत्रांक–01/वि0–15/2023.....1094...../

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

दिनांकः– 08/07/2024

संकल्प

विषयः– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत **Development, Maintenance, Hosting and Implementation of Various Portals (Pay Fixation & Verification System, Learning Management system, Centralized Portal for the DHTE-GoJ, Private University Management Portal, Anudaan – Vitt Rahit Colleges Portal, CM Fellowship Application Portal and Apprenticeship Management Portal); Implementation of NAD/ABC as per NEP 2020, Learning Management System and e-Samarth ERP System through CSC Learning Coordinators; and providing necessary support for Digital Governance in Universities and Colleges of Jharkhand** के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के अधीन **M/s CSC e-Governance Services India Limited** का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं उक्त के कार्यान्वयन हेतु रु0 20,95,40,640/– (बीस करोड़ पंचानबे लाख चालीस हजार छः सौ चालीस) (कर अतिरिक्त) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के लिए तथा विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी और आईसीटी सक्षम उपकरणों का लाभ उठाने की योजना बना रहा है ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और भविष्य की तत्परता में सुधार हो सके तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का सफल कार्यान्वयन किया जा सके।

2. राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को स्वचालित करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड की एक एकीकृत केंद्रीय डिजिटल प्रणाली विकसित करने के लिए एक रोडमैप तैयार करके इसे प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी।

3. इस संबंध में, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के द्वारा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस को एक विस्तृत अध्ययन करने और प्रमुख interventions का प्रस्ताव देने के लिए सहयोग प्राप्त किया गया। इसके अलावा, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस को मौजूदा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और पारदर्शिता में सुधार करने और Physical Touch Points को कम करने के लिए डिजिटल interventions का सुझाव देने की जिम्मेदारी भी दी गई थी।

4. नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस टीम के साथ कई बैठकों में चर्चा के अनुसार सभी आवश्यक संशोधनों के साथ जनवरी 2023 में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा ड्राफ्ट To-be रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

5. नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा पहचाने गए प्रमुख interventions निम्न थेः–

   - विभाग के लिए सामान्य उद्यम संसाधन योजना (ERP) प्रणाली का अभाव।

- भर्ती, पदोन्नति और वेतन निर्धारण से संबंधित अपने पेशेवर विवरण वाले कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का अभाव।
- छात्रों के बीच सीखने की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स (MOOCs) जैसे डिजिटल टूल्स का अभाव।
- राज्य, उच्च शिक्षण संस्थानों की पहुंच और भविष्य की तैयारी में सुधार के लिए ऑनलाइन परीक्षा और प्रॉक्टरिंग प्रणाली का अभाव।
- सभी विभागीय, उच्च शिक्षण संस्थानों और छात्रों से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं की hosting के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म का अभाव।

6. भारत सरकार ने मौजूदा स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की दृष्टि से 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया, जिसे आमतौर पर एनईपी 2020 के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन हेतु विभिन्न डिजिटल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जैसे एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना, Digital Divide को समाप्त करना, ऑनलाईन शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑनलाईन परीक्षा, ऑनलाईन आकलन आदि।

7. झारखण्ड सरकार और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में IT & Digital Infrastructure को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में दिनांक–14.12.2022 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में Student Resource Centre की स्थापना की जाए, जो छात्रों एवं संस्थानों को NEP-2020 के विभिन्न आयामों यथा–Academic Bank of Credit (ABC), National Academic Depository (NAD), SWAYAM तथा MOOCs, Learning Management System हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करे। Student Resource Centre की स्थापना और इसके अपेक्षित कार्यों के संदर्भ में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण हेतु उक्त बैठक में सम्मिलित CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया।

8. उक्त बैठक में NEP-2020 के क्रियान्वयन हेतु नीति आयोग द्वारा पहचाने गये 18 कार्य बिन्दुओं के अनुरुप निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों की पहचान की गई:–

- संस्थानों में चल रहे शैक्षिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, सीखने और विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, प्रलेखन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, असाइनमेंट और वितरण के प्रबंधन में सहायता के लिए शिक्षण प्रबंधन प्रणाली। यह डिजिटल लर्निंग के एक्शन प्वाइंट नंबर D1 के अनुरूप है।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) पर राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों और छात्रों को ऑनबोर्ड करके चार साल के Multiple Entry Multiple Exit Undergraduate Programme को सक्षम और

सुगम बनाना। यह Learner Centric Education के एक्शन पॉइंट नंबर L2 और नंबर L3 के अनुरूप है।

- राज्य के अनुसंधान उत्पादन में सुधार लाने और राज्य में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करना। यह उद्योग–संस्थान लिंकेज के एक्शन प्वाइंट नंबर IC-4 के अनुरूप है।
- राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की सकल नामांकन अनुपात (GER), पहुंच और भविष्य की तैयारी में सुधार के लिए नए बहु–विषयक सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना। यह Learner Centric Education के एक्शन प्वाइंट नंबर L1 के अनुरूप है।
- जवाबदेही स्थापित करने के लिए, वेतन निर्धारण, वित्त रहित महाविद्यालय अनुदान आवेदन आदि जैसे पोर्टलों के माध्यम से एक पारदर्शी और सुचारू प्रशासन प्रक्रिया का निर्माण करना।

9. NEP-2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु दिनांक–16.12.2022 को विभाग में आहूत मल्टी स्टेक होल्डर की बैठक में CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) के द्वारा Student Resource Centre, NAD/ABC हेतु डाटा अपलोड, Learning Management System, Online Education आदि के संदर्भ में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में यह प्रस्तावित किया गया कि CSC-SPV के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में Student Resource Centre स्थापित किया जाए।

10. माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में 27.03.2023 को आयोजित प्रथम कुलपति सम्मेलन में राज्यस्तरीय Learning Management System तथा उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में Digital Infrastructure से युक्त Student Resource Centre स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

11. इसके उपरांत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 15.05.2023 को आहूत NEP-2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में Digital Governance हेतु Digital Infrastructure को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल हस्तक्षेप और पारदर्शी प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली विकसित करने को आवश्यक समझा गया।

12. Digital Governance तथा Digital Infrastructure को सुदृढ़ करने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, आईसीटी सेवाओं जैसे शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के डिजिटल कार्यान्वयन, वेतन निर्धारण और सत्यापन पोर्टल, निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान आवेदन पोर्टल, जैसे कई पोर्टलों का लाभ उठाना चाहता है। साथ ही केंद्रीकृत पोर्टल तैयार करने की योजना है।

13. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को ई–समर्थ (ERP के लिए ई–गवर्नेंस सूट) के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता होगी, शैक्षणिक डेटा जैसे मार्कशीट और वर्तमान के साथ–साथ पिछले छात्रों के प्रमाण पत्र, पिछले छात्रों को दी गई डिग्री आदि को अपलोड करना होगा।

14. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों के बीच उच्च और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और महिला छात्रों के बीच तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता योजना के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, जो एक व्यापक छात्रवृत्ति–सह–फेलोशिप योजना है, तैयार की जा रही है। पूर्ण पारदर्शिता, Access और Turn around Time (TaT) सुनिश्चित करने के लिए, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को आवेदन, सत्यापन और संवितरण प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल की Hosting, Development & Maintenance के लिए सेवाओं की आवश्यकता होती है। यह शैक्षणिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीयकरण के कार्य बिंदु संख्या R1 के अनुरूप है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग शैक्षणिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीयकरण के एक्शन प्वाइंट नंबर R3 के अनुसार एक राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क विकसित करने की प्रक्रिया में भी है।

15. इस क्रम में CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) के द्वारा विभिन्न डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

16. CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में उल्लेखित Scope of Work की विवरणी निम्नवत है:–

I. <u>Pay Fixation and Verification System</u>

CSC SPV proposes to develop and maintain the Pay Fixation and Verification System", so that comprehensive, accurate, reliable, transparent and one stop solution to the Colleges, Universities and the Department. M/s CSC SPV proposes the following scope of work: -

a. Development of a cloud-based software application to register users, enter data, verify their data, processing of data and extract MIS reports for the Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand.

b. Testing and deployment of the developed software at Operation and Execution Level.

c. Training and Knowledge Transfer to the concerned authority at various level.

d. Post Go-Live Maintenance Service like Customization, Enhancement and Support on a monthly maintenance charge basis.

II. <u>Learning Management System</u>

Learning Management System (LMS) is a platform that manages learning and development services in an online mode. It also helps in minimizing dependency on offline infrastructure-based classroom teaching-learning. LMS helps manage administration, documentation, tracking, reporting, assignment and delivery of ongoing educational programs, trainings, or learning and development programs at the institutes.

The broad scope of work for the requirement of DHTE is listed below: -

a. Adaptive learning environment with configuring courses and assignment and mapping it with users enrolled for a course along with validity attribute.

b. Application content management along with active/inactive facility for users.

c. Course creation along with collaboration, certificate generation, tran script generation andactive/inactive feature.

d. Course enrolment along with user's access management on the basis of asynchronous learning.

e. Virtual classroom along with camera surveillance, collaboration, whiteboard, user's access management, validity & Inactive attribute.

f. Online Assignment & assessment creation along with proctoring, certificate, transcript, examination report card/results, user's access management, validity & Inactive option facility.

g. Event based notifications based on the frequency of classes.

h. Enrolled user's courses (Independent course or adaptive learning course) status tracking, assignment & assessment status tracking & virtual classes attendance status tracking.

i. Generation of statistical reports and dashboards for easy reference of Student, University and the Department.

III. <u>Centralized Portal for the DHTE – Govt. of Jharkhand</u>

M/s CSC-SPV shall create a common digital platform for amalgamating all the services and process involving the Department, Universities/ Colleges, students, faculties, and other external stakeholders.

IV. <u>Private University Portal</u>

M/s CSC-SPV shall develop and maintain the Private Universities Portal. In the envisaged portal, M/s CSC-SPV shall enable the following stakeholders and their broad stakeholder wise functionalities: -

Government of Jharkhand

a. Approval of University
b. Issuance of Letter of Intent (LoI)
c. Issuance of Letter of Incorporation
d. Issuance of Letter of Approval (LoA)
e. Appointment of Administrator (In case of dissolution/ derecognition)
f. De-recognition of Private University

Scrutiny Committee

a. Verification of Application
b. Updating of compliance report
c. Recommend for the issuance of Letter of Intent

d. Recommend for the issuance of Letter of Incorporation
e. Recommend for the issuance of Letter of Approval

Sponsoring Body

a. Submission of Application
b. Uploading of Project Report
c. Adherence to the compliance
d. Submission of Bank Guarantee
e. Submission of Application Fee
f. Withdrawal of Application
g. Geo-tagging of the University Location
h. Uploading Images of the Buildings
i. Submission and Uploading Annual Reports
j. Submission of Grievance, if any

Inquiry Authority

a. Submission of inquiry report
b. Submission of Recommendations to the Government of Jharkhand

V. **Anudaan – Vitt Rahit Portal**

Under the Jharkhand State Unaided Institution (Grant) Act, 2004, the Government of Jharkhand provides grant to permanently affiliated institutions (Degree College). The grant is divided into two components namely, recurring expenses and second is non-recurring expenses. Recurring expenses is provided on an annual basis whereas non-recurring expenses is provided as a one-time grant for capital expenditure which includes renovation, construction, and regular maintenance, etc.

The broad scope of work of for M/s CSC-SPV is as follows: -

a. Creation of web based application for the application, scrutiny and approval of the proposal.
b. Creation of unique id for all stakeholders like college, University, Nodal Officer DHTE, Grants Committee DHTE and Drawing Disbursing Officer (DDO), DHTE.
c. Enabling multiple processes for grant of recurring and non-recurring expenses.

VI. **CM Fellowship for Academic Excellence Portal**

M/s CSC-SPV shall work on the development, hosting and maintenance of the web based portal with the following functionalities: -

a. It shall allow multiple application of student under various components of the portal.
b. It shall enable verification of candidature of the students and allow various approving authority for sanctioning of the benefits under the scheme.

c. It shall create a robust mechanism for handing multiple application and multiple insights at a time.

d. It shall enable mechanism for allowing disbursement of fellowship amount to students and reimbursement of bills under the scheme.

VII. Apprenticeship Management Portal

M/s CSC-SPV shall work on the development, hosting and maintenance of the web based portal for the selection and allotment of students, who are applying for apprenticeship with Universities, Colleges and other bodies under the Department.

Stakeholder-wise functionalities of the portal:-

1. Student

a. Registration on the Portal

b. Viewing of jobs on the Portal

c. Application for Jobs on the Portal

d. Choice filing of location in case multiple locations are available for a single job

e. Ability to view provisional allotment of jobs

f. Ability to view final allotment of jobs

g. Ability to withdraw from the selection process

2. Institution

a. Ability to post jobs on the portal

b. Ability to provide post wise, category wise (as per the reservation criteria reservation) break up for each post created by the Institution

c. Ability to enter detailed eligibility criteria and qualifying parameters of the job posting.

d. Ability to view the post wise merit list of students from the list of applied students (auto generation of merit list).

e. Ability to issue provisional offer letter to shortlisted students and update status of the candidate.

f. Ability to issue final offer letter to verified shortlisted student with option to update records on the NATS Portal.

g. Auto - Blocking functionalities for students already selected for the post.

h. Ability to accept applications for multiple posts on the web portal.

3. **Automatic features on the portal**

a. Automatic generation of merit list for category-wise, post wise selection of students

b. Automatic allotment of students as per vacancy status

c. Automatic blocking and unblocking of candidate on selection and withdrawal of seats

d. Automatic matching of candidates as per the qualification posted by the institutions

e. Automatic generation of provisional and final offer letter from the web portal.

VIII. Implementation of NAD/ABC

The Learning Coordinators located in each College/University will assist the administration in the following:

a. Onboarding the Academic Institute on National Academic Depository.

b. Assist the Academic Institute in uploading the certificates/ awards on NAD & ABC.

c. Assist the eligible students in obtaining ABC ID and share it with the Academic Institute.

d. The Learning Coordinators shall prepare a phase wise plan for uploading of legacy academic data of students.

e. They shall assist the students in college/academic admission applications at nominal cost.

IX. Assistance in implementation of e-Samarth ERP Suite

The Learning Coordinators manning the Student Resource Centres (SRC) shall act as technical assistants to the Nodal Officers and Module Admins of the University. They shall act as single stop solution for any implementation related queries and problems of DHTE. They shall also assist the University officials in all ICT related activities. They shall coordinate with the Project Management Unit and DHTE for adherence of timelines envisaged for roll out of eSamarth in Universities.

X. CSC SPVs additional Proposals

a. NIELIT Facilitation Center in all 289 College -

CSCs to facilitate students of Colleges in all Universities of Jharkhand by NIELIT Facilitation Centers. These CSCs in Colleges can do IIBF/NSEIT/BCC/CCC, etc Courses and exams.

b. Students Survey for courses demands and full utilization of CSC Services – CSC SPV will conduct a survey of students in State Universities of Jharkhand as notified by DHTE from time to time for identifying the course requirements of students and their implementation through the education partners.

c. **Industry Linkages and Placements** – CSC SPV will develop a platform for online applications of internships in different industries to enhance skills of the students and also for a common platform for the placements of students. Integration with AICTE Internship Portal. (https://internship.aicte-india.org/)

d. **To run Vocational and Professional (Job Oriented) skills short term courses in College** - CSC SPV will run Vocational (NPTEL / SWAYAM / MOOC) / Professional courses from IIT Bombay, IBM, Microsoft, IDEED, Boston, Infosys, Symbiosis, Google, Bhu - Kaushal, GST, Stock Market, etc. CSC SPV will identify and host free courses on the state implemented LMS/ redirect them for students' easy access. For paid courses, CSC SPV shall charge fees as per the tri-partite agreement between the University, DHTE and CSC-SPV.

e. **Replacement, new appointment of learning coordinator and application development:**

Replacement in case of leave: In case the member of State PMU or learning coordinator of a SRC is on leave, then the State SPOC of CSC-SPV and District Level Education SPOCs of CSC-SPV shall make appropriate arrangements for his/her immediate replacement from the buffer of 10% of total learning coordinators/ state PMU deployed by CSC SPV such that the position of learning coordinator/ state PMU is not vacant even for a single day.

Replacement in case of termination/ resignation/ unauthorized absence: In case the learning coordinator of a SRC is under termination/resignation/unauthorized absence then it shall be the responsibility of the district level education SPOCs of CSC SPV to immediately make arrangements for his/her replacement from the buffer of 10% of total learning coordinators deployed by CSC SPV such that the position of learning coordinator is not vacant even for a single day and take appropriate steps for appointment of new learning coordinators within ten days from termination/resignation/unauthorize absence.

New Appointment: If any request comes from the DHTE, GoJ regarding requirement of SRC at newly established Colleges/Universities apart from 289 colleges and 11 Universities, then CSC- SPV would appoint Learning coordinator at all such newly established Colleges/Universities at the same cost (RS. 5000/- per Learning coordinator per month) as mentioned in the preliminary proposal.

New Application Development: In case new requirements of application/portal development come from the DHTE, GoJ, then CSC-SPV shall develop all such applications at mutually

agreed timelines and well-defined payment milestones. The cost of such development shall be calculated on the basis of the man monthly rate proposed in the preliminary project report.

Integration Services: CSC SPV shall provide necessary support for the integration services of the proposed portals with different technology solutions such as: Payment gateway services, Aadhaar integration etc. and other applications as and when required by DHTE or University for effective implementation of the proposed schemes.

17. CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में उक्त कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु Timeline की विवरणी निम्नवत है-

a. Proposed Project Timeline for Pay Fixation and Verification System, Private University Management Portal, Anudaan – Vitta Rahit College System, CM Fellowship Management System, Apprenticeship Management Portal and Centralized Portal for DHTE – GoJ.

Requirement Study & System Functionality & Real Scope Understanding	7 Days
Project Start up	By 7 Days
Form & Report Designing and Wireframe (Click Through Model) Preparation	By 15 Days
Functional & Technical Architectural Document Submission (Aiming)	By 15 Days
Process Re-engineering Meeting & Adaptation (Aiming)	7 Days
Approval of System Specification Document (Aiming)	By 30 Days
Milestone-1: Showcasing of Menu System & User Interface	By 15 Days
Milestone-2: Showcasing of Functionality in Development Environment (Functionalities with Backend Integration)	By 30 Days
Milestone-3: Showcasing of Forms & Reports in Test Environment (Functionalities With test sample data loading)	By 45 Days
Milestone-4: Final Showcasing of Entire Life Cycle in Production Environment (Functionalities With live sample data loading from userlocations)	By 60 Days
Milestone-5: Go Live & Go To Users Readiness	8 Days

It is estimated that the above portals will Go-Live within 75 days of post signing of contract.

b. Proposed Project Timeline for the Learning Management System

Requirement Study & System Functionality & Real Scope Understanding	By 14 Days
Project Start up	By 14 Days
Form & Report Designing and Wireframe (Click Through Model) Preparation	By 30 Days
Functional & Technical Architectural Document Submission (Aiming)	By 45 Days
Approval of System Specification Document (Aiming)	By 45 Days
Milestone-1: Showcasing of Menu System & User Interface	By 35 Days
Milestone-2: Showcasing of Functionality in Development Environment (Functionalities With Backend Integration)	By 60 Days
Milestone-3: Showcasing of Forms & Reports in Test Environment (Functionalities With test sample data loading)	By 90 Days
Milestone-4: Final Showcasing of Entire Life Cycle in Production Environment (Functionalities With live sample data loading from user locations)	By 120 Days
Milestone-5: Go Live & Go To Users Readiness	By 150 Days

Milestone-6: PMU for Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 1	0-365 days
Milestone-7: PMU for Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 2	366–730 days
Milestone-8: PMU for Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 3	731–1,095 days
Milestone-9: PMU for Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 4	1,096 – 1,460 days
Milestone-10: PMU for Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 5	1,461 – 1,825 days

It is estimated that the Learning Management System will Go-Live within 150 days of post signing of contract and post-delivery PMU and Learning Coordinator support for a period of 5 years.

18. CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में उक्त कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु भुगतेय राशि की विवरणी निम्नवत है-

a. Financial Proposal for the Pay Fixation and Verification System, Private University Management Portal, Anudaan – Vitta Rahit College System, CM Fellowship Management System, Apprenticeship Management Portal and Centralized Portal for DHTE – GoJ.

Sl. No	Budget Item	Unit	Unit Price (Rs.)	Total (Rs.)	Remarks
I. Capital Expenses					
1	**Cost for Development of Pay Fixation and Verification System**				
1a	Team Lead	3	2,62,920	7,88,760	1 Team Lead for 3 Months with 10+ Years' experience at Level 15- T1(A)
1b	Project Tech Manager	3	2,00,320	6,00,960	1 Project Tech Manager for 3 Months with 10+ Years' Experience at Level 13- T1(A)
1c	Business & Functional Analyst/ Subject Matter Expert	1	1,06,420	1,06,420	1 Business Analyst for 1 Months with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
1d	UI/ UX Designer	1	87,640	87,640	1 UI/ UX Designer for 1 Months with 1+ Years' Experience at Level 6- T1(A)
1e	Database Engineer	2	87,640	1,75,280	1 Database Engineer for 1 Months with 1+ Years' Experience at Level 6- T1(A)
1f	Software Engineer/ Web Developer	4	1,06,420	4,25,680	2 Software Engineer/ Web Developer for 2 Months each with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
1g	Software Testing and Other Expenses	1	3,15,260	3,15,260	Software Testing from STQC Empanelled Agencies, Bug Fixing and Other Expenses
Total Capital Expenses				**25,00,000**	

2	**Cost for Development of Private University Management Portal**				
2a	Team Lead	3	2,62,920	7,88,760	1 Team Lead for 3 Months with 10+ Years' experience at Level 15- T1(A)
2b	Project Tech Manager	3	2,00,320	6,00,960	1 Project Tech Manager for 3 Months with 10+ Years' Experience at Level 13- T1(A)
2c	Business & Functional Analyst/ Subject Matter Expert	1	1,06,420	1,06,420	1 Business Analyst for 1 Month with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
2d	UI/ UX Designer	1	87,640	87,640	1 UI/ UX Designer for 1 Months with 1+ Years' experience at Level 6 – T1(A)
2e	Database Engineer	2	87,640	1,75,280	1 Database Engineer for 1 Months with 1+ Years' Experience at Level 6 - T1(A)
2f	Software Engineer/ Web Developer	4	1,06,420	4,25,680	2 Software Engineer/ Web Developer for 2 Months each with 5+ Years' Experience at Level 7 – T1(A)
2g	Software Testing and Other Expenses	1	3,15,260	3,15,260	Software Testing from STQC Empanelled Agencies, Bug Fixing and Other Expenses
Total Capital Expenses				**25,00,000**	
3	**Cost for Anudaan - Vitt Rahit College System**				
3a	Team Lead	2	2,62,920	5,25,840	1 Team Lead for 2 Months with 10+ Years' Experience at Level 15- T1(A)
3b	Project Tech Manager	2	2,00,320	4,00,640	1 Project Tech Manager for 3 Months with 10+ Years' Experience at Level 13- T1(A)
3c	Business & Functional Analyst/ Subject Matter Expert	1	1,06,420	1,06,420	1 Business Analyst for 1 Month with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
3d	UI/ UX Designer	1	87,640	87,640	1 UI/ UX Designer for 1 Months with 1+ Years' Experience at Level 6 – T1(A)
3e	Database Engineer	2	87,640	1,75,280	1 Database Engineer for 1 Month with 1+ Years' Experience at Level 6- T1(A)
3f	Software Engineer/ Web Developer	4	1,06,420	4,25,680	2 Software Engineer/ Web Developer for 2 Months each with 5+ Years' Experience at Level 7 – T1(A)
3g	Software Testing and Other Expenses	1	2,78,500	2,78,500	Software Testing from STQC Empanelled Agencies, Bug Fixing and Other Expenses
Total Capital Expenses				**20,00,000**	

4	Cost for CM Fellowship Portal				
4a	Team Lead	3	2,62,920	7,88,760	1 Team Lead for 3 Months with 10+ Years' Experience at Level 15- T1(A)
4b	Project Tech Manager	3	2,00,320	6,00,960	1 Project Tech Manager for 3 Months with 10+ Years' Experience at Level 13- T1(A)
4c	Business & Functional Analyst/ Subject Matter Expert	1	1,06,420	1,06,420	1 Business Analyst for 1 Months with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
4d	UI/ UX Designer	1	87,640	87,640	1 UI/ UX Designer for 1 Months with 1+ Years' Experience at Level 6- T1(A)
4e	Database Engineer	2	87,640	1,75,280	1 Database Engineer for 1 Months with 1+ Years' Experience at Level 6- T1(A)
4f	Software Engineer/ Web Developer	4	1,06,420	4,25,680	2 Software Engineer/ Web Developer for 2 Months each with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
4g	Software Testing and Other Expenses	1	3,15,260	3,15,260	Software Testing from STQC Empanelled Agencies, Bug Fixing and Other Expenses
Total Capital Expenses				**25,00,000**	

5	Cost for Apprenticeship Management Portal				
5a	Team Lead	2	2,62,920	5,25,840	1 Team Lead for 2 Months with 10+ Years' Experience at Level 15- T1(A)
5b	Project Tech Manager	2	2,00,320	4,00,640	1 Project Tech Manager for 2 Months with 10+ Years' Experience at Level 13- T1(A)
5c	Business & Functional Analyst/ Subject Matter Expert	1	1,06,420	1,06,420	1 Business Analyst for 1 Months with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
5d	UI/ UX Designer	1	87,640	87,640	1 UI/ UX Designer for 1 Months with 1+ Years' Experience at Level 6- T1(A)
5e	Database Engineer	2	87,640	1,75,280	1 Database Engineer for 2 Months with 1+ Years' Experience at Level 6- T1(A)
5f	Software Engineer/ Web Developer	4	1,06,420	4,25,680	2 Software Engineer/ Web Developer for 2 Months each with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
5g	Software Testing and Other Expenses	1	2,78,500	2,78,500	Software Testing from STQC Empanelled Agencies, Bug Fixing and Other Expenses
Total Capital Expenses				**20,00,000**	

6	Cost for Development of Centralized Portal for DHTE				
6a	Team Lead	3	2,62,920	7,88,760	1 Team Lead for 3 Months with 10+ Years' Experience at Level 15- T1(A)
6b	Project Tech Manager	3	2,00,320	6,00,960	1 Project Tech Manager for 3 Months with 10+ Years' Experience at Level 13- T1(A)
6c	Business & Functional Analyst/ Subject Matter Expert	3	1,06,420	3,19,260	1 Business Analyst for 1 Months with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
6d	UI/ UX Designer	1	87,640	87,640	1 UI/ UX Designer for 1 Months with 1+ Years' Experience at Level 6- T1(A)
6e	Database Engineer	2	87,640	1,75,280	1 Database Engineer for 1 Months with 1+ Years' Experience at Level 6- T1(A)
6f	Software Engineer/ Web Developer	6	1,06,420	6,38,520	2 Software Engineer/ Web Developer for 3 Months each with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
6g	Software Testing and Other Expenses	1	3,89,580	3,89,580	Software Testing from STQC Empanelled Agencies, Bug Fixing and Other Expenses
Total Capital Expenses				**30,00,000**	

CAPEX COST: The total estimated cost for the above mentioned systems is **INR 1,45,00,000/-** (Rupees One Crore forty five Lakhs only). Applicable taxes will be levied extra.

b. Financial Proposal for the Learning Management System, e-Samarth (including SIRF, MOCK NAAC tool), NAD / ABC implementation

Sl. No.	Budget Item	Unit	Unit Price (Rs.)	Total (Rs.)	Remarks
I. Capital Expenses					
1	**Cost for Development of the Learning Management System**				
1a	Team Lead	6	3,44,300	20,65,800	1 Team Lead for 3 Months with 15+ Years' Experience at Level 18- T1(A)
1b	Project Tech Manager	18	2,62,920	47,32,560	3 Project Tech Managers for 6 Months each with 10+ Years' Experience at Level 15- T1(A)
1c	Business & Functional Analyst/ Subject Matter Expert	18	1,69,020	30,42,360	3 Business & Functional Analyst/ SME for 6 Months with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
1d	UI/ UX Designer	12	1,06,420	12,77,040	2 UI/ UX Designers for 6 Months each with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)

1e	Database Engineer	18	1,06,420	19,15,560	3 Database Engineers for 6 Months each with 5+ Years' Experience at Level 7- T1(A)
1f	Software Engineer/ Web Developer	120	1,25,200	1,50,24,000	20 Software Engineers/ Web Developers for 6 Months each with 5+ Years' Experience at Level 9- T1(A)
1g	Mobile App Developer	12	1,25,200	15,02,400	2 Mobile App Developers for 6 Months each with 5+ Years' Experience at Level 9- T1(A)
1h	Software Testing, Implementation and Other Expenses	1	24,40,280	24,40,280	Software Testing from STQC Empanelled Agencies, Bug Fixing, Implementation and Other Expenses
Total Capital Expenses				**3,20,00,000**	

The estimated cost for the development of Learning Management System is **INR 3,20,00,000/-** (Rupees Three Crore and twenty Lakhs only). Applicable taxes will be levied extra.

c. Operational and Maintenance Expense

1	**Cost for Operation and Maintenance of the proposed portal for the period of 60 months**				
	Budget Item	**Months**	**Unit Price (Rs.)**	**Total Price (Rs.)**	**Remarks**
1a	Team Lead	60	2,87,960	1,72,77,600	1 Project Consultant for 60 Months with 10+ Years' Experience at Level 16– T1(A)
1b	Project Consultant	60	2,87,960	1,72,77,600	1 Project Consultant for 60 Months with 10+ Years' Experience at Level 16– T1(A)
1c	Database Engineer	60	1,69,020	1,01,41,200	1 Database Engineer for 60 Months with 1+ Years' Experience at Level 7 – T2
1d	Software Engineer/ Web Developer	60	1,69,020	1,01,41,200	1 Software Engineer/ Web Developer for 60 Months with 5+ Years' Experience at Level 11 – T1 (A)
1e	Jr. Software Engineer/ Web Developer	60	1,37,720	82,63,200	1 Jr. Software Engineer/ Web Developer for 60 Months with 5+ Years' Experience at Level 10 – T1 (A)
1f	Software Testing and Other Expenses	4	6,08,550	24,34,200	Software Testing from STQC Empanelled Agencies, Bug Fixing and Other Expenses

1g	Learning Coordinators for implementing the LMS and other college related technical work	60 X 300 =18000	5,000	9,00,00,000	300 Learning Coordinators will provide LMS implementation support and college related technical work for a period of 5 years
1h	Software Engineer/ Web Developer	60	65,094	39,05,640	1 Software Engineer/ Web Developer for 60 Months with 1+ Years' Experience at Level 6 – T2
Total Operational & Maintenance Expenses				**15,94,40,640**	

The estimated cost for the implementation of Pay Fixation & Verification System, Private University Management Portal, Anudaan – Vitt Rahit System, CM Fellowship Management System, Apprenticeship Management Portal, Centralized Portal for DHTE, Learning Management System, Implementation of NAD & ABC and Implementation of e-Samarth System is **INR 15,94,40,640/-** (Rupees Fifteen crore Ninety four lakhs forty thousand six hundrd and forty only). Applicable taxes will be levied extra.

d. Operational and Maintenance Expenses: e-mail service charges (As per actuals)

1	**Cost for e-Mail servic charges, (As per actuals) for the Pay Fixation and Verification System, Private University Management Portal, Anudaan - Vitt Rahit System, CM Fellowship Portal, Apprenticeship Management Portal, Centralized Portal for DHTE and the Learning Management System for a period of 60 months**				
	Budget Item	**Months**	**Unit Price (Rs.)**	**Total Price (Rs.)**	**Remarks**
1a	e-Mail service Charges (as per actuals) –LMS	5,00,00,000	0.05	25,00,000	Estimating an average of 1,00,00,000 eMail per year at a rate of 0.05 paise per eMail. Bill will be as per actuals.
1b	e-Mail service Charges (as per actuals)- other portals (except Apprenticeship Management Portal)	2,00,00,000	0.05	10,00,000	Estimating an average of 40,00,000 eMail per year at a rate of 0.05 paise per eMail. Bill will be as per actuals.
1c	e-Mail service Charges (as per actuals)- Apprenticeship Management Portal	20,00,000	0.05	1,00,000	Estimating an average of 4,00,000 eMail per year at a rate of 0.05 paise per eMail. Bill will be as per actuals.
Total estimated e- Mail Service Charges (as per actuals)				**36,00,000**	

The estimated cost for the e- Mail Service Charges for all applications mentioned above is Rs. 36,00,000 (Thirty Six Lakh only). Applicable taxes will be levied extra.

Note: M/S CSC SPV in its propsal included the cost for hosting the portals on its own server and the SMS gateway charges as well. However, all the applications will be hosted on the State Data Center, Jharkhand. Also, the SMS gateway shall be provided by the Department of Information Technology and e-Governance, Government of Jharkhand, hence their cost has not been considered.

e. **Total Variable Cost:** The estimated total variable cost of Learning Management System, NAD & ABC and e-Samarth, Pay Fixation and Verification System, Private University Management Portal, Anudaan – Vitta Rahit College System, CM Fellowship Management System, Apprenticeship Management Portal and Centralized Portal for DHTE – GoJ is **INR 16,30,40,640/- (Rupees Sixteen Crore Thirty Lakh Forty Thousand Six Hundred Forty only).** Applicable taxes will be levied extra.

f. **Total CAPEX plus Variable Cost:** The estimated total cost of development, implementation, hosting, SMS/e-Mail gateway charges and programme management for the Pay Fixation & Verification System, Private University Management Portal, Anudaan – Vitt Rahit System, CM Fellowship Management System, Apprenticeship Management Portal, Centralized Portal for DHTE, Learning Management System, Implementation of NAD & ABC and Implementation of e-Samarth System are **INR 20,95,40,640/- (Rupees Twenty Crore Ninety Five Lakh Forty Thousand Six Hundred Forty only).** GST will be levied extra as per applicable rates. E- Mail Charges will be charged as per actual.

19. CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में उक्त कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु Payment Milestone की विवरणी निम्नवत है-

a. Payment Milestone for Pay Fixation and Verification System, Private University Management Portal, Anudaan – Vitt Rahit System, CM Fellowship Portal, Apprenticeship Management Portal and Centralized Portal for DHTE

	Timeline	Amount Payable
Delivery Milestone I	T+15 days (T=Date of Agreement)	25% of the Capital Expense
Delivery Milestone 2 + 3 +4	T+ 60 days	50% of the Capital Expense
Delivery Milestone 5 UAT & Final Release	T+ 75 days	25% of the Capital Expense
The operational and maintenance expenses shall be paid on quarterly basis as per actual deployment of resources and actual e-Mail charges for a period of 5 years.		

b. Payment Milestone for Learning Management System

	Timeline	Amount Payable
Delivery Milestone I	T+35 days (T=Date of Agreement)	25% of the LMS Capital Expenses

Delivery Milestone 2	T+ 60 days	25% of the LMS Capital Expenses
Delivery Milestone 3 +4	T +120 days	25% of the LMS Capital Expenses
Delivery Milestone 5 UAT & Final Release	T+ 150 days	25% of the LMS Capital Expenses
The operational and maintenance expenses shall be paid on quarterly basis as per actual deployment of resources, actual e-Mail charges for a period of 5 years.		

20. CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में उक्त कार्यों हेतु Service Uptime Commitment (if hosted on CSC SPV's data center) की विवरणी निम्नवत है-

CSC SPV's scope of the service is limited to the applications developed by the CSC SPV. CSC SPV commits to provide access to the applications on a 95% uptime measured on a quarterly basis. Third party applications or applications integrated from third parties or servers taken from third parties are out of scope. This can't apply to performance issues caused by the following: i) Overall internet congestion, ii) Unavailability of generic internet services due to virus or hacker attacks, iii) Actions or inactions of customer or third parties beyond the control of CSC SPV, iv) Scheduled maintenance, upgrades, urgent security fixes, scheduled downtime, etc.

21. **CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की समीक्षाः–**

विभाग के द्वारा CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की समीक्षा हेतु कार्यालय आदेश सं0 46 सह–पठित ज्ञापांक 903, दिनांक–20.04.2023 द्वारा समिति का गठन किया गया जिसमें Department of IT & e-Governance के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति के द्वारा समीक्षोपरांत निम्न अनुशंसा की गई:–

(i) M/s CSC SPV कम्पनी अधिनियम के तहत स्थापित एक कंपनी है और इसके Majority Stake Holder भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें हैं। M/s CSC SPV कम्पनी में भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें एवं उनके एजेंसी, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को मिलाकर भागीदारी 52.60% है। M/s CSC SPV ने एंटरप्राइज ग्रेड आईसीटी समाधानों के Development, Hosting & Maintenance का एक Proven Track Record भी प्रदर्शित किया है।

M/s CSC SPV द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:–

- PMGDISHA – Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) training of six crore citizens.
- Economic Census – Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI) – Survey of 40 crore household and establishment
- Investor awareness project – Ministry of Law and Justice

- Tele Law – Ministry of Law and Justice
- e-SHRAM-labour registration – Ministry of Labour & Employment

(ii) M/s CSC SPV द्वारा प्रस्तावित Learning Management System (LMS) के संदर्भ में, समिति इस बात से सहमत है कि LMS चल रहे शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रशासन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, असाइनमेंट और वितरण के प्रबंधन में सहायता करेगा। संस्थानों में हितधारकों के लिए प्रशिक्षण, सीखने और विकास कार्यक्रम। यह पहल एनईपी 2020 के डिजिटल लर्निंग के एक्शन प्वाइंट नंबर D1 के अनुरूप भी है। इससे पहुंच में भी सुधार होगा और राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की भविष्य की तैयारी सुनिश्चित होगी।

(iii) M/s CSC SPV द्वारा प्रस्तावित एक अन्य प्रमुख पहल राज्य के 300 उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संसाधन केंद्रों (Student Resource Centre) की स्थापना है। ये Student Resource Centre छात्रों को न केवल नाममात्र की लागत पर आवश्यक छात्र सेवाएँ प्रदान करेंगे, बल्कि M/s CSC SPV द्वारा नियुक्त लर्निंग को–ऑर्डिनेटर भी होंगे। ये समन्वयक 400 गतिविधियों में छात्रों और संकाय सदस्यों की सहायता करेंगे, ABC-NAD और ई–समर्थ के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेंगे और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा आवश्यक आईसीटी से संबंधित सहायता के लिए तकनीकी संसाधन कर्मियों के रूप में कार्य करेंगे। समिति इस बात से सहमत है कि M/s CSC SPV द्वारा प्रदान किया गया यह मानव संसाधन आईसीटी हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

(iv) इसके अलावा M/s CSC SPV उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में एक पांच (5) सदस्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (PMU) स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, वरिष्ठ डेवलपर और डेवलपर्स शामिल हैं, जो LMS और सभी पोर्टल के नियमित रखरखाव के लिए सहायता, निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

(v) वेतन सत्यापन और निर्धारण के संदर्भ में, समिति इस बात से सहमत है कि यह विभाग के लिए लंबे समय से चली आ रही समस्या रही है और इसके कारण वास्तविक कर्मचारियों को लाभ के वितरण में कई कानूनी जटिलताओं में देरी हुई है। विभाग ने पोर्टल की शुरुआत के साथ फास्ट–ट्रैक लाभ, पारदर्शिता में सुधार, Physical Touch Points को कम करने और कानूनी मामलों के सौहार्दपूर्ण निबटारा को सक्षम करने की परिकल्पना की है।

(vi) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में, छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए सूचना का एकल बिंदु स्थापित करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का दीर्घकालिक दृष्टिकोण रहा है। कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अपनी सभी छात्रवृत्ति/फेलोशिप योजनाओं, प्रवेश और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी, विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों की वेबसाइटों के साथ जुड़ाव की मेजबानी करने में सक्षम होगा। यह सूचनाओं के तेजी से प्रसार में भी मददगार होगा।

(vii) निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पोर्टल के संदर्भ में, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एक निजी विश्वविद्यालय अधिनियम बनाने की प्रक्रिया में है, जो राज्य सरकार को सकल

नामांकन अनुपात, Access और उच्च शिक्षण संस्थानों की भविष्य की तैयारी में सुधार के लिए नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। निजी विश्वविद्यालयों का पोर्टल आवेदन, जांच, अनुमोदन और शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।

(viii) मुख्यमंत्री फेलोशिप पोर्टल के संदर्भ में, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों के बीच उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षण संस्थानों स्तर पर शोध को प्रोत्साहित करने और महिला छात्रों के बीच तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना नामक एक व्यापक छात्रवृत्ति–सह–फेलोशिप योजना भी तैयार की है। पोर्टल पूरी पारदर्शिता, Access में आसानी और तेज Turn around Time (TaT) सुनिश्चित करेगा। यह एनईपी 2020 के शैक्षणिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीयकरण के एक्शन प्वाइंट नंबर R1 के अनुरूप भी है।

(ix) अप्रेन्टीस प्रबंधन पोर्टल के संदर्भ में समिति का मंतव्य है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा विभागान्तर्गत अन्य संस्थानों में अप्रेन्टीस प्रशिक्षुओं का चयन करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षुओं के चयन प्रक्रिया को स्वचालित करने हेतु अप्रेन्टीस प्रबंधन पोर्टल की आवश्यकता है। समिति का मंतव्य है कि अप्रेन्टीस प्रबंधन पोर्टल विभाग के लिए आवश्यक है।

(x) वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल के संदर्भ में, बिना किसी डिजिटल हस्तक्षेप के अनुदान प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में न केवल समय लग रहा है, बल्कि निरीक्षण और सत्यापन के कई स्तर भी हैं। पोर्टल उचित आवेदन ट्रैकिंग, परियोजना प्रबंधन और कॉलेजों को अनुदान का वितरण सुनिश्चित करेगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि विभाग के पास सभी अनुदानों के संबंध में जानकारी का एकल बिंदु स्रोत आसानी से उपलब्ध हो।

(xi) ABC/NAD और ई–समर्थ कार्यान्वयन के संदर्भ में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों और छात्रों को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) पर ऑनबोर्डिंग करके चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (एफवाईयूजीपी) को सक्षम और सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना की है। यह Learner Centric Education के एक्शन पॉइंट नंबर L2 और नंबर L3 के अनुरूप है। M/s CSC SPV द्वारा प्रस्तावित एक प्रमुख पहल राज्य के 289 उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संसाधन केंद्रों (Student Resource Centre) की स्थापना है। ये Student Resource Centre छात्रों को न केवल Nominal लागत पर आवश्यक छात्र सेवाएं प्रदान करेंगे, बल्कि 05 वर्षों के लिए M/s CSC SPV द्वारा नियुक्त Learning Co-ordinators भी होंगे। ये समन्वयक 400 से अधिक गतिविधियों में छात्रों और संकाय सदस्यों की सहायता करेंगे, ABC-NAD और ई–समर्थ के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेंगे, उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा आवश्यक आईसीटी से संबंधित सहायता के लिए तकनीकी संसाधन कर्मियों के रूप में कार्य करेंगे।

(xii) समिति का निष्कर्षः

- समिति ने M/s CSC SPV द्वारा प्रस्तावित लागत ब्रेकअप का मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला कि आईसीटी सेवाओं के लिए उद्धृत Man-monthly लागत टीयर 1 (ए) सूचीबद्ध विक्रेताओं के लिए NICSI द्वारा अनुसमर्थित Man-monthly लागत से अधिक नहीं है।
- M/s CSC SPV द्वारा विकसित किए जाने वाले सभी एप्लिकेशन, सिस्टम और पोर्टल को झारखण्ड सरकार के राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) पर होस्ट किया जा सकता है। यदि एसडीसी पर होस्टिंग संभव नहीं है, तो M/s CSC SPV या तो अपने स्वयं के डाटा सेंटर पर या प्रस्ताव में दरों के अनुसार किसी भी MeiTY empanelled cloud सेवा प्रदाता पर पोर्टलों की Hosting कर सकता है।
- SMS सेवाओं के लिए, राज्य सरकार के गेटवे का उपयोग किया जा सकता है और यदि व्यवहार्य नहीं है तो M/s CSC SPV द्वारा प्रस्ताव में विस्तृत दर के अनुसार SMS सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- उपरोक्त सभी कारकों पर विचार करते हुए समिति अनुशंसा करती है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग आईसीटी सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विकल्प के रूप में M/s. CSC SPV पर विचार कर सकता है।

22. अतः CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं विभागीय समिति की अनुशंसा के आलोक में–
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत Development, Maintenance, Hosting and Implementation of Various Portals (Pay Fixation & Verification System, Learning Management system, Centralized Portal for the DHTE-GoJ, Private University Management Portal, Anudaan – Vitt Rahit Colleges Portal, CM Fellowship Application Portal and Apprenticeship Management Portal); Implementation of NAD/ABC as per NEP 2020, Learning Management System and e-Samarth ERP System through CSC Learning Coordinators; and providng necessary support for Digital Governance in Universities and Colleges of Jharkhand के लिए CSC e-Governance Services India Limited के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के अधीन M/s CSC e-Governance Services India Limited का मनोनयन के आधार पर चयन किया जाता है।

23. M/s. CSC SPV के प्रस्ताव में उल्लेखित M/s. CSC SPV के द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न कार्य (उपर्युक्त कंडिका 16) तथा Timeline (उपर्युक्त कंडिका 17) के आलोक में M/s. CSC SPV को निम्न विवरणी के अनुसार कुल रु0 20,95,40,640/– (बीस करोड़ पंचानवे लाख चालीस हजार छः सौ चालीस रूपये) (कर अतिरिक्त) की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती हैः–

a. Financial Proposal for the Pay Fixation and Verification System, Private University Management Portal, Anudaan – Vitta Rahit College System, CM Fellowship Management System, Apprenticeship Management Portal and Centralized Portal for DHTE – GoJ.

Sl.No	Expense Head	Amount (in Rs.)
1	Development of Pay Fixation and Verification System	25,00,000
2	Development of Private University Management Portal	25,00,000
3	Anudaan - Vitt Rahit College System	20,00,000
4	CM Fellowship Portal	25,00,000
5	Apprenticeship Management Portal	20,00,000
6	Development of Centralized Portal for DHTE	30,00,000
	Total	**1,45,00,000**
Rupees One Crore forty five Lakhs only. Applicable taxes will be levied extra.		

b. Financial Proposal for the Learning Management System, e-Samarth (including SIRF, MOCK NAAC tool), NAD/ABC implementation

Sl.No	Expense Head	Amount (in Rs.)
1	Development of the Learning Management System	3,20,00,000
	Total	**3,20,00,000**
Rupees Three Crore and twenty Lakhs only. Applicable taxes will be levied extra.		

c. Operational and Maintenance Expense

Sl.No	Expense Head	Amount (in Rs.)
1	Operation and Maintenance of the proposed portal for the period of 60 months	15,94,40,640
	Total	**15,94,40,640**
Rupees Fifteen crore ninety four lakhs forty thousand six hundred forty only. Applicable taxes will be levied extra.		

d. Operational and Maintenance Expenses: e-mail service charges (As per actuals)

Sl.No	Expense Head	Amount (in Rs.)
1	e-Mail service Charges (as per actuals) –LMS	25,00,000
2	e-Mail service Charges (as per actuals)- other portals	11,00,000
	Total	**36,00,000**
Rupees Thirty Six Lakh only. Applicable taxes will be levied extra.		

e. All the applications will be hosted on the State Data Center, Jharkhand. The Department of IT & e-Governance, Government of Jharkhand sought certain compliances from CSC-SPV for hosting the applications on the State Data Centre. The compliances required by the Department of IT & e-Governance, Government of Jharkhand and response of CSC-SPV vide its letter no.- 23/08/04/JH dated 10/08/2023 is as follows:-

(i) Only virtual/ containerizations environment is available at JH-SDC for deployment of application.
CSC-SPV Response 1: Acceptable, Virtual machines should be provided as per the specifications defined by CSC technical team.

(ii) Latest platform/ technology/ tool is recommended for application development so that the necessary hosting infrastructure may be in-line with the JH-SDC.
CSC-SPV Response 2: Accepted

(iii) Application which has to be hosted on the JH-SDC should be in compliance of Guideline for Indian Government Website (GIGW).
CSC-SPV Response 3: Accepted

(iv) Security audit of the application is mandatory before hosting of application in JH-SDC.
CSC-SPV Response 4: Accepted

(v) Source Code and Intellectual Property Rights (IPR) of the application should be in the name of Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand.
CSC-SPV Response 5: Source codes of the applications shall be deployed and handed over to the department by CSC SPV, IPR may be further applied by the Department of Higher and Technical Education.

(vi) Compliance of periodic security audit is mandatory.
CSC-SPV Response 6: Accepted

(vii) Any specific software which is not available in JH-SDC could not be provided.
CSC-SPV Response 7: CSC-SPV shall procure if need arise and shall be responsible till the O & M period i.e. 05 years.

Hence, CSC-SPV has accepted the required compliances of Department of IT & e-Governance, Government of Jharkhand for hosting the Portals on Jharkhand State data center.

Also, the SMS gateway shall be provided by the Department of Information Technology and e-Governance, Government of Jharkhand.

f. अतः कुल रु0 20,95,40,640/– (बीस करोड़ पंचानवे लाख चालीस हजार छः सौ चालीस रूपये) (कर अतिरिक्त) पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

g. M/s. CSC SPV को उपर्युक्त कंडिका 19 में उल्लेखित Payment Milestone के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।

24. प्रस्तावित राशि राज्य योजना अंतर्गत बजट मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–03 विश्वविद्यालयों को सहायता, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता/796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–BS–निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

25. M/s. CSC SPV, विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा विभाग के मध्य एक Memorandum of Understanding (MoU) हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

26. प्रस्ताव पर दिनांक–19.06.2024 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

2.7.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–01/वि0–15/2023– 1094 /राँची, दिनांकः 08/07/2024
प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2.7.24
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–01/वि0–15/2023– 1094 /राँची, दिनांकः 08/07/2024
प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.7.24
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–01/वि0–15/2023– 1094 /राँची, दिनांकः 08/07/2024
प्रतिलिपि–झारखण्ड राज्य के माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2.7.24
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–01/वि0–15/2023– 1094 /राँची, दिनांकः 08/07/2024
प्रतिलिपि–माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रांची के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

2.7.24
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–01/वि0–15/2023– 1094 /राँची, दिनांकः 08/07/2024
प्रतिलिपि–विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च, शिक्षा/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कुलसचिव, सभी राजकीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड/विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट को ई–गजट में प्रकाशनार्थ/श्री कुमार चन्दन, MIS पदाधिकारी, तकनीकी सहायता समूह को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/बजट शाखा, उच्च शिक्षा/State Head, Jharkhand, M/s CSC SPV को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.24
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुलग्नक – 1

Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding (MoU) entered on the ..... Day of the month of ..... in the Year ..... ("Effective Date").

Among

The Department of Higher and Technical Education (DHTE), Government of Jharkhand is the nodal agency formed to drive all the higher and technical education initiatives of the State to its pinnacle. The Department of Higher and Technical Education, having its office at 3rd Floor, Yojana Bhawan, Nepal House, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002 (hereinafter referred to as **"DHTE"**), which expression shall, unless the context otherwise requires, include its permitted successors and assigns of the **"FIRST PART"**.

AND

CSC e-Governance Services India Limited, a Company incorporated under the Companies Act 1956, having its registered office at Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, Pragati Vihar, New Delhi-110003 (hereinafter referred to as **"CSC-SPV"**) which expression shall mean and includes its successors, permitted assigns of the **"SECOND PART"**.

AND

....., **JHARKHAND** having its office at, ... Jharkhand (hereinafter referred to as **"University"**) which expression, unless repugnant to the context or meaning thereof, shall include its successors and assigns, party of the **THIRD PART**

DHTE, CSC-SPV, and the..... University shall hereinafter be collectively referred to as **"Parties"** and individually as **"Party"**.

WHEREAS

1. The Department of Higher and Technical Education (DHTE), Govt. of Jharkhand is functioning under the administrative control of the Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand, with an aim to take the higher and technical education in the State to its pinnacle.

2. Under the Digital India programme formulated by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), Government of India, the Common Services Centers (CSCs) are conceptualized as ICT-enabled, front-end service delivery points of Government, Social and Private Sector Services in the areas of Government, Agriculture, Health, Education, Financial Services and Utility Payments etc. CSCs are delivering various services to the citizens, especially in Rural India, changing how they learn, communicate, manage their livelihoods and access government services. State Governments across India are leveraging the Common Services Centers for improved access to public services.

3. ..... University, is an autonomous body established by the Government of Jharkhand under Jharkhand State University Act (as amended) to impart quality education and knowledge in the State of Jharkhand.

NOW, THEREFORE, IN CONSIDERATION OF THE PROMISES AND MUTUAL COVENANTS, ALL THE ABOVE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS:

1. Areas of Collaboration:

This MoU sets out the understanding between DHTE and CSC-SPV about the design, development, and implementation of various technology solutions in achieving DHTE's dream of 2030 in higher education of Jharkhand.

2. Objectives

Parties agree that this MoU has been signed with the following objectives:

a. DHTE and CSC-SPV mutually agree to design, develop, and implement seven technology solutions;

b. DHTE will share the functional requirement specifications of the following 7 (seven) technology systems (hereinafter referred as seven technology solutions) with CSC-SPV:

   1. Pay Fixation and Verification System
   2. Private university management portal
   3. Anudaan – Vitt Rahit College System
   4. CM Fellowship Portal
   5. Centralized Portal for DHTE
   6. Learning Management System, Implementation of NAD and ABC and E Samarth (including SIRF and MOCK NAAC Tool)
   7. Apprenticeship Management Portal

c. CSC-SPV will develop and submit a proposal towards the design, development, and implementation of above mentioned seven technology solutions;

d. DHTE will consider the proposal submitted by CSC-SPV and issue necessary work order/ G.O. towards the development and implementation of the seven technology solutions;
e. CSC-SPV will deploy necessary manpower to understand the requirement of DHTE for all the seven technology solutions, development of software requirement specifications for each of the seven technology solutions, wireframe designing and get the approval of DHTE for each of the seven technology solutions, development of the solution in testing environment and demonstration to DHTE to get feedback for each of the seven technology solutions, Implement the feedback if any for each of the seven technology solutions, and Deployment of the solution in the live environment for each of the seven technology solutions;
f. CSC-SPV will submit the revised timeline and milestone for each of the seven technology solutions after the requirement study and in consultation with the DHTE post signing of this MoU;
g. DHTE will release the payment to CSC-SPV as per the agreed Milestones mentioned in **Schedule – I** of this MoU. Any deviation in the Milestones will be mutually discussed and agreed;
h. CSC-SPV will deploy around 300 Learning Coordinators in each of the Universities and Colleges for setting-up CSC and offering CSC services in each of the identified universities/ colleges, assisting the administration in onboarding their respective institution in National Academic Depository (NAD) and assist the students in generating their Academic Bank of Credit (ABC) ID, etc.;
i. CSC-SPV shall maintain a surplus of 10% of the total Learning Coordinators deployed at any given point of time for any provision as enumerated under Section 9 of this MoU;
j. CSC-SPV through its learning coordinators shall ensure the full implementation of E-Samarth ERP Suite in all State Universities; and
k. CSC-SPV will setup a Programme Management Unit (PMU) consisting of technical and operational manpower to support the implementation of these seven technology solutions over a period of five years as detailed in **Schedule-II** of this MoU.
l. CSC-SPV shall maintain a surplus of 10% of the total PMU deployed at any given point of time for any provision as enumerated under Section 14 of this MoU.

3. Scope of Work

The scope of work as agreed by Parties for each technological intervention shall be as follows:-

I. Pay Fixation and Verification System

CSC SPV proposes to develop and maintain the Pay Fixation and Verification System", so that comprehensive, accurate, reliable, transparent and one stop solution to the Colleges, Universities and the Department. CSC SPV proposes the following scope of work: -

a. Development of a cloud-based software application to register users, enter data, verify their data, processing of data and extract MIS reports for the Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand.

b. Testing and deployment of the developed software at Operation and Execution Level.

c. Training and Knowledge Transfer to the concerned authority at various level.

d. Post Go-Live Maintenance Service like Customization, Enhancement and Support on a monthly maintenance charge basis.

II. Learning Management System

Learning Management System (LMS) is a platform that manages learning and development services in an online mode. It also helps in minimizing dependency on offline infrastructure-based classroom teaching-learning. LMS helps manage administration, documentation, tracking, reporting, assignment and delivery of ongoing educational programs, trainings, or learning and development programs at the institutes.

The broad scope of work for the requirement of DHTE is listed below: -

a. Adaptive learning environment with configuring courses and assignment and mapping it with users enrolled for a course along with validity attribute.

b. Application content management along with active/inactive facility for users.

c. Course creation along with collaboration, certificate generation, transcript generation and active/inactive feature.

d. Course enrolment along with user's access management on the basis of asynchronous learning.

e. Virtual classroom along with camera surveillance, collaboration, whiteboard, user's access management, validity & Inactive attribute.

f. Online Assignment & assessment creation along with proctoring, certificate, transcript, examination report card/results, user's access management, validity & Inactive option facility.

g. Event based notifications based on the frequency of classes.

h. Enrolled user's courses (Independent course or adaptive learning course) status tracking, assignment & assessment status tracking & virtual classes attendance status tracking.

i. Generation of statistical reports and dashboards for easy reference of Student, University and the Department.

III. Centralized Portal for the DHTE – Govt. of Jharkhand

CSC-SPV shall create a common digital platform for amalgamating all the services and process involving the Department, Universities/ Colleges, students, faculties, and other external stakeholders.

IV. Private University Portal

CSC-SPV shall develop and maintain the Private Universities Portal. In the envisaged portal, CSC-SPV shall enable the following stakeholders and their broad stakeholder wise functionalities: -

Government of Jharkhand

a. Approval of University
b. Issuance of Letter of Intent (LoI)
c. Issuance of Letter of Incorporation
d. Issuance of Letter of Approval (LoA)
e. Appointment of Administrator (In case of dissolution/ derecognition)
f. De-recognition of Private University

Scrutiny Committee

a. Verification of Application
b. Updating of compliance report
c. Recommend for the issuance of Letter of Intent
d. Recommend for the issuance of Letter of Incorporation
e. Recommend for the issuance of Letter of Approval

Sponsoring Body

a. Submission of Application
b. Uploading of Project Report
c. Adherence to the compliance
d. Submission of Bank Guarantee
e. Submission of Application Fee
f. Withdrawal of Application
g. Geo-tagging of the University Location
h. Uploading Images of the Buildings
i. Submission and Uploading Annual Reports
j. Submission of Grievance, if any

Inquiry Authority

a. Submission of inquiry report
b. Submission of Recommendations to the Government of Jharkhand

V. Anudaan – Vitt Rahit Portal

Under the Jharkhand State Unaided Institution (Grant) Act, 2004, the Government of Jharkhand provides grant to permanently affiliated institutions (Degree College). The grant is divided into two components namely, recurring expenses and second is non-recurring expenses. Recurring expenses is provided on an annual basis whereas non-recurring expenses is provided as a one-time grant for capital expenditure which includes renovation, construction, and regular maintenance, etc.

The broad scope of work of for CSC-SPV is as follows: -

a. Creation of web based application for the application, scrutiny and approval of the proposal.

b. Creation of unique id for all stakeholders like college, University, Nodal Officer DHTE, Grants Committee DHTE and Drawing Disbursing Officer (DDO), DHTE.

c. Enabling multiple processes for grant of recurring and non-recurring expenses.

VI. **CM Fellowship for Academic Excellence Portal**

CSC-SPV shall work on the development, hosting and maintenance of the web based portal with the following functionalities: -

a. It shall allow multiple application of student under various components of the portal.

b. It shall enable verification of candidature of the students and allow various approving authority for sanctioning of the benefits under the scheme.

c. It shall create a robust mechanism for handing multiple application and multiple insights at a time.

d. It shall enable mechanism for allowing disbursement of fellowship amount to students and reimbursement of bills under the scheme.

VII. **Apprenticeship Management Portal**

CSC-SPV shall work on the development, hosting and maintenance of the web based portal for the selection and allotment of students, who are applying for apprenticeship with Universities, Colleges and other bodies under the Department.

Stakeholder-wise functionalities of the portal:-

1. **Student**
   a. Registration on the Portal
   b. Viewing of jobs on the Portal
   c. Application for Jobs on the Portal
   d. Choice filing of location in case multiple locations are available for a single job
   e. Ability to view provisional allotment of jobs
   f. Ability to view final allotment of jobs
   g. Ability to withdraw from the selection process

2. **Institution**
   a. Ability to post jobs on the portal

b. Ability to provide post wise, category wise (as per the reservation criteria reservation) break up for each post created by the Institution

c. Ability to enter detailed eligibility criteria and qualifying parameters of the job posting.

d. Ability to view the post wise merit list of students from the list of applied students (auto generation of merit list).

e. Ability to issue provisional offer letter to shortlisted students and update status of the candidate.

f. Ability to issue final offer letter to verified shortlisted student with option to update records on the NATS Portal.

g. Auto - Blocking functionalities for students already selected for the post.

h. Ability to accept applications for multiple posts on the web portal.

3. Automatic features on the portal

a. Automatic generation of merit list for category-wise, post wise selection of students

b. Automatic allotment of students as per vacancy status

c. Automatic blocking and unblocking of candidate on selection and withdrawal of seats

d. Automatic matching of candidates as per the qualification posted by the institutions

e. Automatic generation of provisional and final offer letter from the web portal.

VIII. Implementation of NAD/ABC

The Learning Coordinators located in each College/University will assist the administration in the following:

a. Onboarding the Academic Institute on National Academic Depository.

b. Assist the Academic Institute in uploading the certificates/ awards on NAD & ABC.

c. Assist the eligible students in obtaining ABC ID and share it with the Academic Institute.

d. The Learning Coordinators shall prepare a phase wise plan for uploading of legacy academic data of students.

e. They shall assist the students in college/academic admission applications at nominal cost.

IX. Assistance in implementation of e-Samarth ERP Suite

The Learning Coordinators manning the Student Resource Centres (SRC) shall act as technical assistants to the Nodal Officers and Module Admins of the University. They shall

act as single stop solution for any implementation related queries and problems of DHTE. They shall also assist the University officials in all ICT related activities. They shall coordinate with the Project Management Unit and DHTE for adherence of timelines envisaged for roll out of eSamarth in Universities.

X. **Support to be made available through College level Students Resource Centres:**

a. **NIELIT Facilitation Center in all 289 College -**

CSCs to facilitate students of Colleges in all Universities of Jharkhand by NIELIT Facilitation Centers. These CSCs in Colleges can do IIBF/NSEIT/BCC/CCC, etc Courses and exams.

b. **Students Survey for courses demands and full utilization of CSC Services** – CSC SPV will conduct a survey of students in State Universities of Jharkhand as notified by DHTE from time to time for identifying the course requirements of students and their implementation through the education partners.

c. **Industry Linkages and Placements** – CSC SPV will develop a platform for online applications of internships in different industries to enhance skills of the students and also for a common platform for the placements of students. Integration with AICTE Internship Portal. (https://internship.aicte-india.org/)

d. **To run Vocational and Professional (Job Oriented) skills short term courses in College** - CSC SPV will run Vocational (NPTEL / SWAYAM / MOOC) / Professional courses from IIT Bombay, IBM, Microsoft, IDEED, Boston, Infosys, Symbiosis, Google, Bhu - Kaushal, GST, Stock Market, etc. CSC SPV will identify and host free courses on the state implemented LMS/ redirect them for students' easy access. For paid courses, CSC SPV shall charge fees as per the tri-partite agreement between the University, DHTE and CSC-SPV.

X (A). Replacement, new appointment of learning coordinator and application development:

Replacement in case of leave: In case the member of State PMU or learning coordinator of a SRC is on leave, then the State SPOC of CSC-SPV and District Level Education SPOCs of CSC-SPV shall make appropriate arrangements for his/her immediate replacement from the buffer of 10% of total learning coordinators/ state PMU deployed by CSC SPV such that the position of learning coordinator/ state PMU is not vacant even for a single day.

Replacement in case of termination/ resignation/ unauthorized absence: In case the learning coordinator of a SRC is under termination/resignation/unauthorized absence then it shall be the responsibility of the district level education SPOCs of CSC SPV to immediately make arrangements for his/her replacement from the buffer of 10% of total learning coordinators deployed by CSC SPV such that the position of learning coordinator is not vacant even for a single day and take appropriate steps for appointment of new learning coordinators within ten days from termination/resignation/unauthorize absence.

New Appointment: If any request comes from the DHTE, GoJ regarding

requirement of SRC at newly established Colleges/Universities apart from 289 colleges and 11 Universities, then CSC- SPV would appoint Learning coordinator at all such newly established Colleges/Universities at the same cost (RS. 5000/- per Learning coordinator per month) as mentioned in the preliminary proposal.

New Application Development: In case new requirements of application/ portal development come from the DHTE, GoJ, then CSC-SPV shall develop all such applications at mutually agreed timelines and well-defined payment milestones. The cost of such development shall be calculated on the basis of the man monthly rate proposed in the preliminary project report.

Integration Services: CSC SPV shall provide necessary support for the integration services of the proposed portals with different technology solutions such as: Payment gateway services, Aadhaar integration etc. and other applications as and when required by DHTE or University for effective implementation of the proposed schemes.

4. Role of DHTE:

a. Share the functional requirement specifications for all the seven technology solutions to be developed by CSC-SPV;
b. Approve the proposal submitted by CSC-SPV towards the development of seven technology solutions;
c. Nominate the concerned expert for the functional study to be organized by CSC-SPV;
d. Approve the software requirement specifications (SRS) and the wireframes submitted by CSC-SPV;
e. Review and give feedback on the developed application in the testing environment and give go ahead on the User Acceptance Test (UAT);
f. Provide the production environment for the applications developed by CSC-SPV;
g. Provide space and infrastructure which include only electricity and furniture for the Programme Management Unit to be deployed by CSC-SPV at a convenient location of DHTE;
h. Ensure that the Learning Coordinators are given space and infrastructure which include only electricity and furniture in the identified universities/ colleges for setting up CSCs and encourage the administration to make use of these Learning Coordinators for the implementation of NAD and ABC in their institution; and
i. Release the payment against deliverables mentioned in the milestones and the invoice submitted by CSC-SPV as per MoU.

5. Role of CSC-SPV:

a. Understand the functional requirement documents shared by DHTE and prepare a proposal and submit it to DHTE for its consideration and approval;

b. Undertake the scoping and functional study along with the expert nominated by DHTE for each of the seven technology solutions;
c. Develop and submit the software requirement specifications and wireframes for each of the seven technology solutions and submit it to DHTE for its approval;
d. Develop the applications as per the approved software requirement specifications and wireframes;
e. Demonstrate the developed applications to DHTE in the testing environment and take feedback for improvement;
f. Perform the Vulnerability Assessment and Penetration Testing through a STQC empanelled agency;
g. Deploy the final tested and approved applications in the production environment provided by DHTE;
h. Identify and Deploy the Programme Management Unit personnel at the DHTE identified location to ensure the smooth implementation of the project;
i. Identify and Deploy 300 Learning Coordinators in the identified Universities and Colleges for setting CSCs and offering CSC services. Also, support the administration in the implementation of NAD and ABC in their respective institution;
j. Provide handholding support to University/College officials in the implementation of E-Samarth modules;
k. Conduct the third party security audit of the seven technology solutions as and when required by DHTE or University in case of application security breach or system failure;
l. CSC SPV shall provide necessary support for the integration services of the proposed portals with different technology solutions such as: Payment gateway services, Aadhaar integration etc. and other applications as and when required by DHTE or University for effective implementation of the proposed schemes; and
m. Raise the tax invoice against each of the deliverables mentioned in the Milestone to DHTE;
n. Submit technology enabled monthly attendance report of all learning coordinators deployed in SRC and members of the State PMU deployed at DHTE.
o. Development of Mobile-based app for proposed portals.

6. <u>Roles of University:</u>

1. Utilize the portals to be developed CSC-SPV;
2. Provide support to the CSC-SPV for data capturing and data verification on timely basis;
3. Provide infrastructure support such as sitting space, furniture, electricity, and internet connectivity for smooth operation of the student resource centre (SRC) to be established by CSC-SPV;
4. Coordinate with CSC-SPV in proper implementation of ABC in the University and Colleges;
5. Facilitate the CSC-SPV in the development of the portals;

6. Seek assistance from CSC-SPV in implementation of E-Samarth ERP Suite.
7. Conduct User Acceptance Testing (UAT) of the portals developed by CSC-SPV, if required; and
8. If required, to verify the work done by CSC-SPV.

7. Financials

The total capital cost for the development of seven technology solutions is **INR 4,65,00,000/** (Rupees Four Crore Sixty Five Lakh only) and the operational and maintenance cost of the project for the period of five years is **INR 15,94,40,640/-**(Rupees fifteen crore ninety four lakhs forty thousand and six hundred forty only). Apart from these capital and operational costs, e-Mail service Charges (as per actuals) the tentative estimate is **INR 36,00,000/-** (Rupees Thirty Six Lakhs only). **The approximate total cost of the project is INR 20,95,40,640 /- (Rupees Twenty Crore Ninety Five Lakh Forty Thousand Six Hundred Forty only). Applicable taxes will be levied extra.**

Charges of cloud hosting and SMS Gateway will be managed by DHTE directly.

It is to be noted that any major change in the functional requirement and architecture or any new application development apart from the one mentioned above will be mutually discussed and agreed by the parties and the cost will be worked out based on the functional requirements.

Summary of Capital expenditure and operational expenditure:

Portal development Capital expenditure, cost and timeline			
SN	Application Name	Cost	Timeline
1	Pay Fixation and Verification System	25,00,000	75 Days
2	Private University Affiliation Portal	25,00,000	75 Days
3	Anudaan - Vitt Rahit College System	20,00,000	75 Days
4	CM Fellowship Portal	25,00,000	75 Days
5	Centralized Portal for DHTE	30,00,000	75 Days
6	Learning Management System	3,20,00,000	150 Days
7	Apprenticeship Management Portal	20,00,000	75 Days
	Total	**4,65,00,000**	
Operational expenditure of portal and timeline			
SN	Application Name	Cost	Timeline
1	Cost for Operation and Maintenance seating of PMU of the proposed portal and Implementation of NAD/ ABC, e-Samarth ERP services, ICT related services through Learning coordinators established at college for a period of 60 months	15,94,40,640	150 Days
2	e-Mail service Charges (as per actuals)	36,00,000	
	Total	**16,30,40,640**	
Total cost of Capex and Opex		**20,95,40,640**	
Cost in word- Twenty crore ninety-five lakhs forty thousand six hundred forty rupees only			

8. Service Level Agreement (SLA) and Penalties

The table below summarizes the performance indicators for the services to be offered by CSC-SPV:

Sl. No.	SLA Terms	Description
1	Uptime	'Uptime' refers to network backbone availability across various segments of Portals and LMS hosted on State Data Centre (SDC) "%Uptime" means ratio of 'up time' (in minutes) in a month to Total time (in minutes) in the month multiplied by 100. The Uptime will be considered for the application part only and not for activities for which SDC is responsible.
2	Not keeping manpower	If CSC-SPV does not deploy the required specified quantity & quality of manpower as per preliminary project proposal or a person deployed is not reporting to the duty, there would be a penalty per person per day as defined in below table and will be deducted from the total cost. A maximum buffer time of 10 days is being provided to CSC-SPV for making the replacement of the manpower, post which the penalty will be imposed as mentioned in table below.
3	Incidence Resolution	• 50% of the Incidents - Within 24 hrs • 75% of the Incidents - Within 48 hrs • 100% of the Incidents - Within 72 hrs • Note: Incidents will be logged in the Helpdesk and CSC-SPV will provide a reference ticket number for the same. CSC-SPV shall resolve the incident and provide necessary updates through the Help Desk and co-ordinate with the stakeholders. Root Cause should be identified for all incidents. • Requests (like password reset, etc.) will be logged in the Helpdesk and CSC-SPV will have to resolve the request and provide necessary updates through the Help Desk and co-ordinate with the stakeholders
4	Application Security Breach	• Detection of security Breach - within 30 minutes • Mitigation of Security Breach - within 1 hr from the time of Breach • Note: Adherence of all the security compliances suggested by the Audit Agency during the security audit of the application. If any security breach in the application is found and suggested compliances haven't been followed than the applicable penalty will be levied.

CSC-SPV shall be paid the applicable charges on delivery milestone basis as per the agreement for the services being provided to the DHTE. The overall penalty would be capped at 15% of payment for each delivery milestone.

In addition to the applicable penalty and the provisions pertaining to closure/termination of contract, DHTE shall be within its rights to undertake termination of contract if or anytime the penalty reaches to 15 % of the milestone payment. Penalty will be calculated on milestone basis.

Appropriate Penalties will be recovered from the milestone payment if CSC-SPV is not able to achieve required Service levels as mentioned below:

Sl. No.	SLA	Target	Penalties
1	Delay in implementation: development and deployment of application	As per Implementation Timelines (Milestones)	• 0.75% of Total Cost for the particular milestone per week or part thereof for delay in implementation subject to maximum of 15% of the total cost for the particular milestone. • Once the maximum penalty reached, DHTE may terminate the contract of CSC-SPV
2	Not keeping required manpower	As per SLA	• Management level staffs stationed at State Level: 1500/- per day per person for un-sanctioned leave or non-reporting at workplace for more than 3 Days and non replacement beyond 10 Days • For Learning Coordinators: 250/- per day per person for un-sanctioned leave or non-reporting at workplace for more than 3 Days and non replacement beyond 10 days • Above charges are in addition to deduction of actual wages for the period of absence based on the rate schedule
3	Delay in resolution of support/incidents for the applications developed by CSC-SPV	As per SLA	• 50% of the Incidents - Within 24 hrs. 0.1% of the Quarterly Payment for every 5% of the unresolved incidents in case 50% of the incidents is not resolved within 24 hrs; • 75% of the Incidents - Within 48 hrs. 0.1% of the Quarterly Payment for every 5% of the unresolved incidents in case 75% of the incidents is not resolved within 48 hrs; • 100% of the Incidents - Within 72 hrs. 0.1% of the Quarterly Payment for every 5% of the unresolved incidents in case 100% of the incidents is not resolved within 72 hrs.

4	Uptime of all IT Software components & services under scope	95.00% (at each individual component level)	For each component 94.51-94.90 - 1.0% of Quarterly Payment; 94.10-94.50 - 2.0% of Quarterly Payment and so on. If the uptime goes below 94.00%, additional penalty of 1% will be charged on Quarterly Payment for each slab 1% downtime.
5	Application Security Breach	As per SLA	0.25% of Quarterly Payment for every single security breach.

In case of justifiable cause presented by CSC-SPV in writing to the DHTE and accepted by the DHTE, the penalty for delay in any service as per SLA may be waived off at the sole discretion of the DHTE.

Note: A Committee shall be formed at Department of Higher and Technical Education consisting of Department officials, representatives from State Universities and CSC-SPV for monitoring of development of all portals and LMS. It shall also be the final authority for determination of any or all forms of changes in the scope of work and levy of penalties, if any.

The Committee will also be liable to recommend the payment of the bills after appraising the deliverables against the milestone

9. Service Uptime Commitment

Scope of the service is limited to the applications developed by the CSC-SPV. CSC-SPV shall ensure to provide access to the applications on a 95% uptime measured on a quarterly basis. Third party applications or applications integrated from third parties or servers taken from third parties are out of scope. This can't apply to performance issues caused by the following: i) Overall internet congestion, ii) Unavailability of generic internet services due to virus or hacker attacks, iii) Actions or inactions of customer or third parties beyond the control of CSC-SPV, iv) Scheduled maintenance, upgrades, urgent security fixes, scheduled downtime, etc.

10. Coordination

All the parties will identify a Single Point of Contact (SPOC) from their respective side for the interaction and coordination on all matters relating to the work described under this MoU.

11. Indemnity

Either Party shall indemnify and hold harmless the other Party for all losses incurred in connection with any third-party claim, except to the extent finally judicially determined to have resulted primarily from the fraud or bad faith of such defaulting Party.

12. Intellectual Property Rights

All final plans, drawings, specifications, designs, reports and other documents submitted by the CSC-SPV in the performance of the services shall become and remain the property of the DHTE, provided payments are timely made by DHTE of all outstanding dues to CSC-SPV including the fee.

Despite anything to the contrary elsewhere contained in this MoU, the intellectual property rights in all methodologies, processes, analysis and recommendations (including but not limited to any presentations made in respect thereof and/or related thereto), frameworks, know-how and techniques used by CSC-SPV in providing services hereunder that (a) existed prior to delivery of the Services, and/or (b) are developed during and/or independently of providing the services, along with all improvements, enhancements and modifications to any or all of the foregoing shall vest with CSC-SPV.

Neither Party shall by virtue of this MoU gain any right to intellectual property of other Party. By entering this MoU, Parties hereto agree not to use other Party's intellectual property without prior written consent.

13. Limitation of Liability

In no event shall either of the parties of this MoU be liable to each other for consequential, indirect, special, incidental, or punitive loss, damage or expense (including without limitation, loss of profits, loss of contracts, loss and corruption of data, loss or damage to reputation and/or goodwill, opportunity costs, etc.) even if the parties have been advised of their possible existence.

14. Replacement and Reappointment of State PMU and Learning Coordinators

a. **Replacement in case of leave:** In case the member of State PMU or learning coordinator of a SRC is on leave, then the State SPOC of CSC-SPV and District Level Education SPOCs of CSC-SPV shall make appropriate arrangements for his/her immediate replacement such that the position of learning coordinator is not vacant even for a single day.

b. **Replacement in case of termination/resignation/unauthorized absence:** In case any of the member of State PMU or the learning coordinator of a SRC is under termination/resignation/unauthorized absence then the State Level SPOCs and District level education SPOCs of CSC-SPV shall make appropriate arrangements for his/her replacement respectively such that the position of member of State PMU and learning coordinator is not vacant even for a single day and take appropriate steps for appointment of member of State PMU and new learning coordinator within ten (10) days from the date of **termination/resignation/unauthorized absence.** The replacement for the State PMU member should be at same or above experience and qualification.

c. **New Appointment:** If any request from the DHTE, GoJ regarding additional requirement of SRC at newly established Colleges/Universities apart from the current 289 colleges and 11 Universities, then CSC- SPV would appoint Learning Coordinators at all such newly established Colleges/Universities at the same cost (Rs. 5000/- per Learning coordinator per month) as mentioned in the proposal.

15. Development of New Web Application

In case CSC-SPV receives any new requirement for portal/application development from DHTE, it shall develop all such applications/portals at mutually agreed timelines and well-defined payment

milestones. The cost of all such development and maintenance shall be calculated on the basis of the man monthly rate proposed in this proposal.

16.Jurisdiction

This MoU shall be governed by and construed in accordance with the laws of India and the Courts of Ranchi, Jharkhand shall have the jurisdiction.

17.Technical Integration

Wherever necessary, DHTE will facilitate the API integration with various Govt. and non-Govt. entities like Chancellor Portal, State Informatics Centre, etc.

18.Terms & Termination

This MoU shall commence on the date of execution of this MoU and continue in full force for 5 (five) years unless terminated by the Parties as per the provision of this MoU. Either Party may terminate this MoU upon 90 (ninety) days written notice sent by registered post acknowledgement to the other party. In the event of termination, a termination plan shall be mutually agreed upon to manage the orderly wind-down of the project within the notice period. All plans, proposals, drawings, Business Requirement Documents (BRD), Functional Requirement Specifications (FRS), SRS, source code, database, etc. belongs to DHTE and upon termination of this agreement CSC-SPV shall transfer all the documents, knowledge and know-how of the portals to DHTE or any other vendor appointed by DHTE.

19.Dispute Resolution & Arbitration clause

If any dispute or difference arises with this MoU, mutual discussions between DHTE, University and CSC-SPV shall settle the same. However, if any unresolved dispute persists, it would be referred to a joint committee of the DHTE, University and CSC-SPV, and the committee's resolution would be final and binding on both Parties.

Any unresolved dispute or difference whatever arising between the Parties to this MoU out of or relating to the Scope, Operation or effect of this MoU or the validity of the breach thereof shall be referred to an Arbitration Panel to be jointly appointed by the Secretary, DHTE, Registrar of the University and Managing Director, CSC-SPV. The provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 will be applicable, and the award made there under the law. Then such difference shall be deemed a submission of Arbitration under the Arbitration and Conciliation Act 1996 or any modifications, Rules or re-enactments thereof. The Arbitration proceedings will be held at Ranchi, Jharkhand. The three parties shall equally bear the cost of arbitration.

20. Provisions for Modifications

The parties agree to make suitable amendment and modifications to this MoU by mutual agreement as per necessity, provided that no modifications, amendment or variation of any provision of this Agreement shall be effective unless the same has been approved in writing by each of the parties. Any reference to this MoU shall be construed as a reference to such agreement, as the same may from time to time be amended, varied, modified, supplemented.

21. Data Protection & Privacy

The term "Data" (which shall include the term "Information") shall have the meaning as defined in the "The Digital Personal Data Protection Act 2023, Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules of 2011 under the Information Technology Act of 2000 (hereinafter referred to as "IT Act & Rules of 2000") as well as local jurisdictional law or under any law defined under Law.

CSC - SPV understand that the person so providing and/or supplying the Data is classified to be highly sensitive under the laws and carries serious legal implications in the event the Data is leaked and/or compromised in any manner whatsoever either manually, operationally and technologically. In view thereof, the Implementing agency herein understand and agree to ensure the Data shall be provided by the person so providing and/or supplying such Data is providing the same, (a) only upon first receiving "Individual Consents" from the Persons(s) to whom this Data belongs, with well-defined and documented "Consent Management Process" in place, (b) with an "express documented statement" that the Data so being provided and/or supplied is with the "Express Written Consent" of the Person, and as per compliances of the Applicable laws in India .

Accordingly the Parties so receiving the said Data shall ensure well-defined "Data Lifecycle Protection Mechanism" (including Data Collection, Processing, Storing, Sharing and Purging Environment) is in place in terms of Data Protection and Privacy Policy, Individual Contributor Statements (wherever required), Trainings to Employees handling the Data, and Data Protection & Privacy Tools to ensure "Data Leakage Prevention" are in place to ensure there is no scope for leakage and/or compromising of Data either manually, operationally and technologically, thereby making the Data so received "Safe and Secure". The Parties shall ensure the secrecy and confidentiality of all the Data so collected / exchanged, and shall not store or keep or share the Data except as per provision of applicable law. This Clause shall survive termination or expiry of this MoU.

22. Provisions for Extension of Agreement

This Agreement may be extended upon mutual written agreement between the parties hereto. Any extension shall be in writing and shall be signed by all the parties. The extension shall specify the duration of the extension period and any additional terms or conditions that may apply during the extended period.

The extension shall be deemed effective upon the expiration of the initial term or any previously agreed-upon extension period. All terms and conditions of the Agreement shall remain in full force and effect during the extension period, unless otherwise specified in the extension agreement.

Either Party may propose an extension by providing written notice to the Other Party, at least 90 days prior to the expiration of the current term or extension period. The proposed extension shall include the desired duration and any proposed modifications or amendments to the Agreement.

23. Severability

If any part, term or provision of this Agreement is held to be illegal, in conflict with any law or otherwise invalid, the remaining portion or portions shall be considered severable and not be affected by such determination, and the rights and obligations of the parties shall be construed and enforced as if the Agreement did not contain the particular part, term or provisions held to be illegal or invalid.

24. Confidentiality

Both the parties recognize, accept and agree that all tangible and intangible information obtained/received/gained/developed or disposed to other party and/or its officers and/or its employees, including but not limited to operations, each party employees, employees' profiles or other information relating to the past, present or future recruitment activities of each party all confidential or proprietary concepts, documentation, reports, lists, files, data, specifications, databases, data files, information, know-how and trade secrets, which may or may not have been patented or a copyright obtained thereof. (Hereinafter collectively referred to as "Confidential Information)

It is understood by both the parties that:

a. During fulfilling its terms and conditions, both the parties shall not disclose in any / all Confidential Information received from other party that it may receive or obtain while carrying out the Services mentioned this Agreement. This clause shall survive the termination of the Agreement.

b. The Compensation details and the terms contained therein are Confidential Information and shall be used by both the parties only for the purposes of billing, accounting.

c. Both the parties shall provide for any / all records maintained as MIS called for by other parties during the course of this Agreement.

25. Force Majeure

Neither Party shall be responsible for any failure to perform due to unforeseen circumstances or to cause beyond their reasonable control, including but not limited to acts of God, regulations of Government, earthquakes, floods, epidemics, war, revolutions, strikes, lockouts, explosion, natural calamities, riot, embargoes, acts of civil or military authorities, fire, accidents, terrorist activities etc. If any Force Majeure event occurs, the affected Party will give prompt written notice to the Other Party and will put reasonable efforts to minimize the impact of such an event.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have signed this MoU hereunder on the dates respectively mentioned against the signature each.

For and on behalf of DHTE:	**For and on behalf of CSC-SPV:**	**For and on behalf of .....University:**
Signature	Signature	Signature
Name	Name	Name
Designation	Designation	Designation
Date	Date	Date
In the presence of:	**In the presence of:**	**In the presence of:**
Signature	Signature	Signature
Name	Name	Name
Designation	Designation	Designation
Date	Date	Date

Proposed Project Timeline: Pay Fixation and Verification System, Private University Management Portal, Anudaan – Vitta Rahit College System, Apprenticeship Management portal, CM Fellowship Management System and Centralized Portal for DHTE – GoJ

Requirement Study & System Functionality & Real Scope Understanding	7 Days
Project Start up	By 7 Days
Form & Report Designing and Wireframe (Click Through Model) Preparation	By 15 Days
Functional & Technical Architectural Document Submission (Aiming)	By 15 Days
Process Re-engineering Meeting & Adaptation (Aiming)	7 Days
Approval of System Specification Document (Aiming)	By 30 Days
Milestone-1: Showcasing of Menu System & User Interface	By 15 Days
Milestone-2: Showcasing of Functionality in Development Environment (Functionalities With Backend Integration)	By 30 Days
Milestone-3: Showcasing of Forms & Reports in Test Environment (Functionalities With test sample data loading)	By 45 Days
Milestone-4: Final Showcasing of Entire Life Cycle in Production Environment (Functionalities With live sample data loading from userlocations)	By 60 Days
Milestone-5: Go Live & Go To Users Readiness	8 Days

It is estimated that the Pay Fixation and Verification System will Go-Live within 75 days of post signing of contract.

Proposed Project Timeline for the Learning Management System

Requirement Study & System Functionality & Real Scope Understanding	By 14 Days
Project Start up	By 14 Days
Form & Report Designing and Wireframe (Click Through Model) Preparation	By 30 Days

Functional & Technical Architectural Document Submission (Aiming)	By 45 Days
Approval of System Specification Document (Aiming)	By 45 Days
Milestone-1: Showcasing of Menu System & User Interface	By 35 Days
Milestone-2: Showcasing of Functionality in Development Environment (Functionalities With Backend Integration)	By 60 Days
Milestone-3: Showcasing of Forms & Reports in Test Environment (Functionalities With test sample data loading)	By 90 Days
Milestone-4: Final Showcasing of Entire Life Cycle in Production Environment (Functionalities With live sample data loading from userlocations)	By 120 Days
Milestone-5: Go Live & Go To Users Readiness	By 150 Days
Milestone-6: PMUfor Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 1	0-365 days
Milestone-7: PMUfor Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 2	366 –730 days
Milestone-8: PMUfor Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 3	731 – 1,095 days
Milestone-9: PMUfor Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 4	1,096 – 1,460 days
Milestone-10: PMU for Technical and Administrative and Learning Coordinator Support for Year 5	1,461 – 1,825 days

It is estimated that the Learning Management System will Go-Live within 150 days of post signing of contract and post-delivery PMU and Learning Coordinator support for a period of 5 years.

Schedule -I: Payment Milestone

1. Payment Milestone for Pay Fixation and Verification System, Private University Management Portal, Anudaan – Vitt Rahit System, Apprenticeship Management portal, CM Fellowship Portal, and Centralized Portal for DHTE

	Timeline	Amount Payable
Delivery Milestone 1	T+ 15 Days (T= Date of agreement)	25% of the Capital Expense
Delivery Milestone 2 + 3 +4	T+ 60 days	50% of the Capital Expense
Delivery Milestone 5 **UAT & Final Release**	T+ 75 days	25% of the Capital Expense
The operational and maintenance expenses shall be paid on quarterly basis as per actual deployment of resources, actual cloud hosting charges and actual SMS/e-Mail charges for a period of 5 years.		

2. Payment Milestone for Learning Management System

	Timeline	Amount Payable
Delivery Milestone 1	T+ 35 Days (T= Date of agreement)	25% of the LMS Capital Expenses
Delivery Milestone 2	T+ 60 days	25% of the LMS Capital Expenses
Delivery Milestone 3 +4	T +120 days	25% of the LMS Capital Expenses
Delivery Milestone 5 **UAT & Final Release**	T+ 150 days	25% of the LMS Capital Expenses
The operational and maintenance expenses shall be paid on quarterly basis as per actual deployment of resources, actual cloud hosting charges and actual SMS/e-Mail charges for a period of 5 years.		

Schedule – II: Programme Management Unit

The details of Programme Management Unit (PMU) consisting of technical and operational manpower to support the implementation of all the technological solutions are as follows: -

1	Cost for PMU for maintenance of the proposed portal for the period of 60 months				
	Budget Item	Months	Unit Price (Rs.)	Total Price (Rs.)	Remarks
1a	Team Lead	60	2,87,960	1,72,77,600	1 Project Consultant for 60 Months with 10+ Years' Experience at Level 16– T1(A)
1b	Project Consultant	60	2,87,960	1,72,77,600	1 Project Consultant for 60 Months with 10+ Years' Experience at Level 16– T1(A)
1c	Database Engineer	60	1,69,020	1,01,41,200	1 Database Engineer for 60 Months with 1+ Years' Experience at Level 7 – T2
1d	Software Engineer/ Web Developer	60	1,69,020	1,01,41,200	1 Software Engineer/ Web Developer for 60 Months with 5+ Years' Experience at Level 11 – T1 (A)
1e	Jr. Software Engineer/ Web Developer	60	1,37,720	82,63,200	1 Jr. Software Engineer/ Web Developer for 60 Months with 5+ Years' Experience at Level 10 – T1 (A)
1f	Software Testing and Other Expenses	4 nos.	6,08,550	24,34,200	Software Testing from STQC Empanelled Agencies, Bug Fixing and Other Expenses
1g	300 Learning Coordinators for implementing the LMS and other college related technical work	18000 (60 months X 300 nos.)	5,000	9,00,00,000	300 Learning Coordinators will provide LMS implementation support and college related technical work for a period of 5 years
1h	Software Engineer/ Web Developer	60	65,094	39,05,640	1 Software Engineer/ Web Developer for 60 Months with 1+ Years' Experience at Level 6 – T2
Total Operational & Maintenance Expenses				**15,94,40,640**	